कचरे की सफाई से रोशन होते शहर

अनिरुद्ध चतुर्वेदी/ कोबरा टीम

कभी देश का मैंचेस्टर कहलाने वाला कानपुर शहर आज चमड़े के कारखानों की वजह से औद्योगिक नगरी के रूप में पहचाना जाता है। चमड़े की टेनरियों से घिरे इस शहर को चमड़ा उद्योग ने नई पहचान जरूर दी लेकिन इस नई पहचान के साथ कानपुर को कचरे का शहर भी कहा जाने लगा। जिन गलियों में कभी पुराना कानपुर दिखता था वहां कचरे के ढ़ेर नजर आने लगे। नगर निगम से लेकर प्रदेश सरकार ने इस औद्योगिक नगरी के कायाकल्प के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन समय गुजरता गया और इन प्रयासों की असफलता के बीच यह शहर गंदगी के नए रिकार्ड स्थापित करता गया। आलम ये हो गया कि कानपुर रहने की दृष्टि से स्वच्छता के मामले में देश के शहरों के 390वें पायदान पर पहुंच गया। लेकिन गत चार सालों में इस शहर ने स्वच्छता के नए आयाम स्थापित किए हैं, जो संभव हुआ है नई तकनीक से बने ग्रीन एनर्जी प्लांट्स की बदौलत। दशकों से कानपुर को कचरे की समस्या से निजात दिलाने में असफल रहे सरकारी प्रयास को सफल बनाने का यह कारनामा कर दिखाया है निजी क्षेत्र की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ए2जेड ने। ये कंपनी देश की उन तमाम कंपनियों में एक है जो म्युनिसपिल सॉलिड वेस्ट यानी कि शहरों से निकलने वाले दैनिक कचरे के निस्तारण का काम करतीं है। इन कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकी न केवल शहरों को कचरे से मुक्त बना रहीं है बल्कि उस कचरे से बिजली और जैविक खाद का उत्पादन भी करतीं हैं। जो कचरा पॉलीथिन, कागज, गत्ते, प्लास्टिक, कांच, कपड़े व रसोई से निकलने वाले कूड़े के रूप में हमारे घरों से निकल कर हमारे वातावरण को गंदा करता था, वही कचरा अब सस्ती बिजली उत्पादन और जैविक खाद बनाने के काम आने लगा है। अब तक जिन शहरों में कचरा प्रबंधन की योजनाएं शुरू हुई उन शहरों की स्वच्छता के स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। निजी कंपनियों के कूडा एकत्र करने के व्यवस्थित तरीकों से कूड़ा प्रबंधन करने में उन शहरों के नगर निगमों से काम का बोझ कम हुआ है। कूड़ा प्रबंधन कंपनियों के कर्मचारी घरों के दरवाजे पर जाकर कूड़ा-कचरा लेते हैं। इस कचरे को एकत्र कर कंपनी अपने प्लांट पर बने डंपिंग ग्राउंड पर ले जातीं है। जहां इस कचरे को कार्बनिक व अकार्बनिक कचरे के रूप में छांटा जाता है। इसके बाद कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग के बाद रिसाइकिल करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

म्युनिसपिल कचरे से बिजली बनाने के लिए एशिया का सबसे बड़ा प्लांट यूपी के कानपुर शहर में लगा है। इस संयंत्र से प्रतिदिन करीब 1500 टन कचरे को रिसाइकिल किया जा सकता है। वर्ष 2008 में ए2जेड कंपनी ने केंद्र सरकार की जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना के अंतर्गत कानपुर में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू किया था। बतौर औद्योगिक शहर कानपुर की सफाई व्यवस्था की दुर्दशा किसी से भी छुपी नहीं रही। लेकिन इस प्लांट के काम शुरू करने के बाद कानपुर की गिनती देश के बीस स्वच्छ महानगरों में होने लगी। कानपुर की इस उपलब्धि को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहा गया। वर्ष 2010 में कानपुर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कचरा निस्तारण के मामले में देश का सबसे बेहतर शहर होने का अवार्ड दिया। जिसके बाद यूपी के वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़ और मुरादाबाद में

वर्ष 2008 में ए2जेड कंपनी ने केंद्र सरकार की जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना के अंतर्गत कानपुर में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू किया था। बतौर औद्योगिक शहर कानपुर की सफाई व्यवस्था की दुर्दशा किसी से भी छुपी नहीं रही। लेकिन इस प्लांट के काम शुरू करने के बाद कानपुर की गिनती देश के बीस स्वच्छ महानगरों में होने लगी।

भी यूपी सरकार व स्थानीय निकाय प्रशासन की मदद से ऐसे संयत्र लगाए गए। जिसके बाद पंजाब, गुजरात और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी इस कंपनी को ऐसे ही संयन्त्र लगाने का प्रस्ताव दिया।

कचरा प्रबंधन में ए 2जेड कंपनी के अधिकारी अपने अनुभव को बताते हुए कहते है कि उनकी कंपनी दुनिया की बेहतरीन तकनीकी के साथ देश को कचरे और बिजली की कमी की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य के साथ इस क्षेत्र में आई है। दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकी और उच्च कार्यक्षमता वाले प्लांटों का प्रयोग करने वाली यह कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव रखती है और भारत समेंत यूरोप, अमेरिका और चीन में अपने उपक्रमों का सफल संचालन कर रही है। कंपनी की सेवाओं को देखते हुए उसे भारत के कई राज्यों में कचरे से बिजली बनाने के उपक्रम लगाने के प्रस्ताव मिल रहे हैं।

आसान नहीं है राहें

कहते है कि हर काम में मुश्किलें जरूर आती है। ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी के कुछ महानगरों में शुरू हुई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजनाओं में। सरकारी सहयोग से म्युनिसपिल वेस्ट को खत्म करने का जिम्मा उठाने के लिए सामने आई निजी कंपनियों के सामने भी कई मुश्किलें आ रहीं है। जैसा कि हम आपको बता चुके है कि कानपुर शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की सफलता को भारत ही नहीं विश्व भर में सराहा गया। लेकिन कानपुर का ही यह प्लांट सफलता के बावजूद दम तोड़ता नजर आ रहा है। जिसकी वजह है इस प्लांट को लगाने वाली कंपनी को कानपुर नगर निगम से मिलने वाली अर्थिक मदद को रोका जाना। कानपुर नगर निगम और कंपनी के बीच हुए अनुबंध के मुताबिक नगर निगम को इस कंपनी को प्रतिवर्ष 80 करोड़ रुपए कचरा उठाने के शुल्क के रूप में चुकाना तय हुआ था। लेकिन गत् एक वर्ष से कंपनी को नगर निगम ने कोई भुगतान नहीं किया है। जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी अपने कर्मचारियों को न तो वेतन दे पा रही है और न ही अपने कचरा उठाने वाले वाहनों को नियमित रूप से संचालित कर पा रही है। कंपनी का कहना है कि बैंकों ने भी उसकी साख पर ऋण देने से मना कर दिया है। कंपनी के लिए पूरे शहर का कचरा उठा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्लांट में भी कचरे की आपूर्ति न होने की वजह से बिजली उत्पादन का कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है। नगर निगम के इस रवैये को लेकर कंपनी कई बार स्थानीय नेताओं और राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री से बैठक कर चुकी है, लेकिन अब तक नतीजा सिफर ही रहा है। कंपनी के मुताबिक सरकारी सहयोग से यूपी के कानपुर शहर से शुरू हुई इस योजना को वर्ष 2010 में मिली सफलता के बाद कंपनी ने वर्ष 2011 में अन्य राज्यों में अपने प्लांट लगाने के प्रस्तावों पर काम शुरू कर दिया था। मौजूदा समय में कंपनी इन राज्यों में अपने प्लांट्स के निर्माण का कार्य लगभग पूरा कर चुकी है। कंपनी जल्द ही पंजाब के

www.pardaphash.com

लुधियाना, जालंधर, गोवा और अहमदाबाद में अपने प्लांट शुरू करने जा रही है।

महानगरों से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को डंप करने के लिए डंपिंग जोन्स बनाने से लेकर उसकी रिसाइकिलिंग के लिए सरकारें कई सौ एकड़ जमीन और करोड़ों रुपए के बजट का आवंटन प्रतिवर्ष करती है। केवल कानपुर की ही बात करें तो कानपुर नगर निगम वर्ष 2006 के आंकडों के मुताबिक करीब 150 करोड़ रुपए का खर्चा केवल शहर के कूड़ाघरों से कचरा उठाने और डंपिंग जोन्स तक पहुंचाने के लिए करता है। इसके बावजूद शहरवासियों को सड़कों और गलियों के मुहानों पर लगे कूड़े के ढ़ेरों से होकर अपना रास्ता बनाना पड़ता था। वहीं जब से ए2जेड ने कानपुर शहर में घरेलू कचरे को उठाने की जिम्मेदारी उठाई तो कानपुर नगर निगम को इस कार्य के लिए कंपनी को वार्षिक तौर पर केवल 80 करोड रुपए चुकाने पड़ते हैं। कंपनी ने अपने खर्चे के लिए बाकी का शुल्क उन घरों से वसूला जिनका कचरा उठाने के लिए कंपनी के कर्मचारी जाते थे। घरेलू कचरा, अस्पतालों, संस्थानों, फैक्ट्रियों और सड़कों की सफाई के बाद निकलने वाले कचरे को कंपनी ने कूड़ा घरों से उठाना शुरू किया। इस कचरे से कंपनी ने बिजली और कार्बनिक खाद का उत्पादन किया। कई टन कचरे को रिसाइकिल करने के बाद बचे अवशेष को भी कंपनी ने प्रयोग में लाते हुए टाइल्स बनाए। पूरी तरह निस्तारण के बाद बचे 20 फीसदी अवशेष को वैज्ञानिक तरीके से लैंड फिल बनाने का काम किया।

सुधरता जीवन स्तर

विकास के मायनों से देखें तो पश्चिमी देशों की तुलना में भारत स्वच्छता के स्तर पर उनसे बहुत पीछे है। सड़कों पर गंदगी की भरमार के साथ अतिक्रमण, उसमें मुंह मारते अवारा जानवरों के बीच भिनभिनाती मक्खियां भारत के आम जनजीवन की जटिलताओं की कहानी कहते नजर आते है। जिसकी बहुत बड़ी वजह हमारी जनसंख्या और आम आदमी की इन तमाम रोजमर्रा की समस्याओं के प्रति उदासीनता मानी जा सकती है। इन्हीं कारणों को सामने कर स्वच्छता अभियानों की तमाम सरकारी योजनाए एक-एक कर ठंडे बस्ते में चली जातीं है। वहीं निजी कंपनियों की मदद से शुरू हो रहीं कचरा निस्तारण की ये नई प्रणाली अब तक सफल मानी जा रही है। म्युनिसपिल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां शहरी कूड़े कचड़े को न केवल हटा रहीं है बल्कि उनके उपयोग से देश के विकास की नई परिभाषा भी गढ़ रहीं है। जो घरेलू अपशिष्ट पदार्थ कल तक हमारे परिवेश में बीमारी और दूषित पर्यावरण के कारक थे, वे आज रिसाइकिल होकर कार्बनिक खाद के रूप में हमारे खेतों में पहुंच कर उत्पादन क्षमता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो कचरा हमारे घरों से निकलकर सड़कों पर फैलकर गंदगी बढ़ता था वही कचरा अब हमारे घरों और सड़कों को रोशन करने के लिए बिजली बनाने के काम आ रहा है।

कचरा निस्तारण करने वाली कंपनी प्रत्येक घर से कूडा उठाने के शुल्क के रूप में 50 रुपए वसूलती है। मासिक रूप से बसूले जाने वाले इस शुल्क को भरने वाले अधिकांश लोग अपने घर से निकलने वाले पूरे कचरे को एक कूड़ेदान में भर कर रखते हैं, और सुबह एक सफाईकर्मी उनके घर आकर उस कूड़े को लेकर जाता है। ये प्रक्रिया कानपुरवासियों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। नतीजतन कानपुर की गलियों में अब कूड़े के ढ़ेर नजर नहीं आते। कानपुरवासी अपनी गलियों की सफाई के प्रति स्वयं जागरुक हो चुके हैं। निजी अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंटस व अस्पतालों के मालिक भी इस बदलाव की वजह से अपने आस पास के परिवेश की स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी म्युनिसपिल वेस्ट निस्तारण की इस योजना को मिले लोगों के समर्थन को देखते हुए उनसे वसूले जाने वाले सर चार्ज को बिजली बिल के साथ समायोजित कर दिया है।

डंपिग जोन्स से मिलेगा छुटकारा

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की ही बात की जाए तो केवल दिल्ली से निकलने वाले घरेलू कचरे के लिए तीन बड़े डंपिंग जोन्स बनाए गए है। इन डंपिंग जोन्स में प्रति दिन कई सौ टन कचरा नगर निगम की गाड़ियों से पहुंचाया जाता है। इसके बावजूद कई सौ टन कचरा राजधानी की कॉलोनियों में बने ढलावों में सड़ता रहता है। आमतौर पर नगर निगम निर्धारित दिनों में ही इन ढ़लावों को खाली करने में सक्षम है। प्रतिदिन निकलने वाले इस कचरे की वजह से दिल्ली के डम्पिंग जोंस में कचरे के कई फीट ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए है। साल दर साल इन डंपिंग जोंस का आकार बढ़ता जा रहा है। बरसात के दिनों में ये डंपिंग जोन्स बीमारियों को जन्म देने वाले साबित होते है और लाखों लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित करते है। देखा जाए तो दिल्ली की बढ़ती आबादी के हिसाब से ये डंपिंग जोन्स आने वाले समय में बेहद छोटे पड़ेंगे और नगर निगम को करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर के कचरे को शहर के बाहर तक पहुंचाने में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। वहीं वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के माध्यम से होने वाले कचरा निस्तारण के रूप में दिल्ली शहर की इस बड़ी समस्या का स्थाई हल मिलता नजर आ रहा है। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में दो कूडा निस्तारण प्लांट लगवाने की योजना को मूर्तरूप देने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली में पश्चिमी देशों के तर्ज पर इस तरह की योजना सरकार द्वारा लाई गई थी, लेकिन कई सौ करोड़ के सरकारी खर्च के बाद बने प्लांट की असफलता के बाद सरकारी उपक्रम को ताला लगा दिया गया। इस असफल प्रयोग के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी राजस्व की बरबादी को रोकने के लिए सरकार को निर्देश दिए कि वह आगे से इस प्रकार की योजनाओं के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से कोई उपक्रम लगाए। जिस पर अमल करते हुए दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी ए2जेड की सहायता से कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र लगाने का फैसला लिया है।

क्या कहते हैं आंकड़े ?

म्युनिसपिल सॉलिड वेस्ट कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका सामना केवल भारत जैसे प्रगतिशील देश कर रहे हैं। आंकड़ों पर जाएं तो अमेरिका के लिए यह समस्या सबसे बड़ी है जहां प्रतिदिन करीब छह लाख 21 हजार टन म्युनिसिपल वेस्ट निकलता है। अमेरिका और भारत के जनसंख्या अंतर को देखते हुए भारत के लिए कचरा निस्तारण एक छोटी समस्या है, क्योंकि यहां प्रतिदिन करीब एक लाख 60 हजार टन म्युनिसपिल वेस्ट निकलता है, जिसमें सबसे ज्यादा म्युनिसपिल वेस्ट कोलकाता शहर से निकलता है। कोलकाता शहर से प्रतिदिन करीब 12 हजार 60 टन कचरा निकलता है जिसमें से मात्र सात सौ टन कचरे का निस्तारण जैविक खाद बनाकर किया जाता है। कोलकाता के बाद मुबंई शहर का नंबर आता है जहां से प्रतिदिन 11 हजार छह सौ टन कचरा प्रतिदिन निकलता है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस मामले में तीसरे स्थान पर है जहां से प्रतिदिन 11 हजार पांच सौ टन कचरा डंपिंग जोन्स में भेजा जाता है। इस क्रम में अगले शहर क्रमशः चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू, पुणे, अहमदाबाद, कानपुर, सूरत, कोची और जयपुर है। इन सभी शहरों से प्रतिदिन कई हजार टन म्युनिसपिल कचरा निकलता है। भारत के अलावा ब्राजील, मैक्सिको और चीन तीन अन्य विकासशील देश है जो सॉलिड वेस्ट की समस्या का सामना कर रहे देशों की सूची के शीर्ष दस में स्थान रखते हैं।

ये है म्युनिसपिल वेस्ट निस्तारण का वर्तमान तरीका-

देश की तमाम बड़ी नगर निगम म्युनिसपिल वेस्ट के निस्तारण के लिए एक ही आम तरीका अपनाती है, लैंड फिलिंग। नगर निगम द्वारा शहर के बाहर ऐसे स्थान चिह्नत किए जाते हैं जहां गड्ढ़ों को भरने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। वहीं नगर निगम के सफाई कर्मचारी कूड़े को उठाने और उसे डंपिंग जोन्स तक पहुंचाने की मशक्कत से बचने के लिए सड़क के किनारे ही कूड़े का ढ़ेर लगाकर उसमें आग लगा देते हैं। जिसके बाद बचा हुआ कूड़ा इलके की गंदगी को बढ़ाता रहता है। आमतौर पर नगर निगम के अधिकारी कचरे को डंपिंग जोंस तक पहुंचाने का काम कागजी तौर पर करते है। न तो नगर निगमों के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी है और न ही ऐसे वाहन जिनसे कचरे को शहर के बाहर पहुंचाया जा सके। गिने चुने कचरा ढ़ोने वाले वाहन है जिनका प्रयोग डंपिंग के लिये किया जाता है। इन गिने चुने वाहनों पर भी सफाई कर्मियों की मनमानी चला करती है। वे भी इन वाहनों को चलाने के बदले ऊपरी आमदनी करना पसंद करते है जिसके लिए कूड़ा ढ़ोने वाले वाहनों के डीजल को निकाल कर बेंच कर निगम कर्मी अपनी जेबें गरम कर लेते है। नतीजतन शहर का कचरा शहर में ही रहता है और सरकारी कागजों में ये काम सफलता पूर्वक अंजाम दिया जाता है।

म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट की योजनाओं की शुरूआती सफलता को देखते हुए कहा जा सकता है कि रोज सुबह घर से दफ्तर से निकलते समय आपको बस या टैक्सी के इंतजार में किसी कचरे के ढ़ेर के पास खड़ा नहीं होना पड़ेगा। न ही आपके घर के सामने की कार पार्किंग क्म चरा पार्क की तरह नजर आएगी। हमारे शहर भी पश्चिमी देशों के उन शहरों की तरह साफ दिखेंगे जिन्हें टेलीविजन पर देखकर हम खुद को पिछड़ा महसूस करते है। ये सब केवल सरकारी या किसी सफाई कंपनी के काम करने से संभव नहीं हो सकता इसके लिए हमारी जागरुकता भी मायने रखती है। ■